भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3504
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लंबित परियोजनाएं

3504. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर, बड़ी संख्या में लंबित परियोजनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत आवासों को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) पंजाब में से कितने लाभार्थियों को पीएमएवाई -जी के अंतर्गत कोई किस्त प्राप्त हुई है और उन लाभार्थियों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिन्हें अंतिम किस्त के लिए अभी भी प्रतीक्षा है; और

(ग) क्या सरकार के पास उन लाभार्थियों के लिए भूमि उपलब्धता के मुद्दे का समाधान करने की कोई योजना है जो भूमि की कमी के कारण आवासों का निर्माण करने में असमर्थ हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक अगले पांच वर्षों में पीएमएवाई-जी के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण करने का अनुमोदन प्रदान किया है ताकि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

यह मंत्रालय पीएमएवाई-जी के तहत निगरानी और आवासों का निर्माण समय पर पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहा है:

- i राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन।
- ii वर्कफ़्लो सक्षम लेनदेन-आधारित एमआईएस-आवाससॉफ्ट , विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड और अन्य आईटी टूल और नवीनतम एआई/एमएल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आवास स्वीकृति और निर्माण पूरा करने की सूक्ष्म निगरानी।
- iii मंत्री/सचिव/उप महानिदेशक द्वारा नियमित समीक्षा।
- iv उच्च लक्ष्यों वाले राज्यों की अलग से समीक्षा।
- v राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर निधियां जारी करना और आगे लाभार्थियों को निधियां जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- vi गुणवत्तापूर्ण आवासों के शीघ्र निर्माण के लिए प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्रियों का दल उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण।
- vii आवास+ 2024 मोबाइल ऐप सहित नए शुरू किए गए आईटी टूल का उपयोग करना जो आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के साथ पारदर्शी लाभार्थी पहचान सुनिश्चित करता है।
- viii एक ही स्थान पर महत्वपूर्ण जानकारी और संसाधनों को समेकित करके पीएमएवाई - जी तक पहुंच को सुव्यवस्थित करने के लिए आवास सखी मोबाइल ऐप तैयार किया गया है।
- ix विशिष्ट निष्पादन सूचकांक डैशबोर्ड के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों और ब्लॉकों को पुरस्कार प्रदान करना , जिससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा पैदा होती है।

(ख): पंजाब राज्य को 1,03,674 (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 63,985 सहित) का कुल लक्ष्य आवंटित किया गया है। इनमें से राज्य द्वारा 55,744 आवास स्वीकृत किए गए हैं और 48,761 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई है। इसके अलावा , अंतिम किस्त की प्रतीक्षा कर रहे लाभार्थियों की संख्या 4,882 है (40,786 लाभार्थियों द्वारा दूसरी किस्त प्राप्त की गई है- 35,904 लाभार्थियों द्वारा तीसरी किस्त प्राप्त की गई है)। दिनांक 12.12.2024 की स्थिति के अनुसार कुल 38,484 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

(ग): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। आवासों के निर्माण के लिए भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को भूमि प्रदान करना सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि वे पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में सबसे अधिक पात्र लाभार्थियों में से हैं। इसलिए , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऐसे लाभार्थी को सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि (पंचायत की सामान्य भूमि , सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित भूमि) सहित किसी अन्य भूमि से भूमि प्रदान की जाए। भूमिहीन लाभार्थियों को परिवारों की रैंकिंग में भी प्राथमिकता दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल 3,63,164 भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि/सहायता प्रदान की गई है।

यह मंत्रालय भूमिहीन लाभार्थियों के लिए आवास निर्माण में तेजी लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठा रहा है:-

क. भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

ख. भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने या भूमि क्रय के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ग. भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए आवाससॉफ्ट में एक वेब एप्लिकेशन विकसित किया गया है , ताकि भूमि आवंटन और गृह निर्माण की प्रगति की आसानी से निगरानी की जा सके।

घ. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित करने का भी अनुरोध किया गया था , जिसमें सचिव (राजस्व) और पीएमएवाई-जी से संबंधित सचिव शामिल हों, ताकि पीएमएवाई-जी के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से भूमि आवंटित की जा सके। इस मामले को माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास) द्वारा सर्वाधिक भूमिहीन लाभार्थियों वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी उठाया गया है।

ड. कई राज्य सरकारें पीएमएवाई-जी के तहत भूमिहीन लाभार्थियों के लिए योजनाएं लागू कर रही हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

i. **बिहार:** बिहार राज्य में मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना लागू की गई है। इस योजना में पात्र लाभार्थियों को अपने आवासों के निर्माण के लिए भूमि खरीदने हेतु 60,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ii. **ओडिशा:** ओडिशा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 'वसुदा' योजना का उद्देश्य ओडिशा में भूमिहीन गरीबों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों और कमजोर समूहों को भूमि अधिकार और आवास लाभ प्रदान करना है।

iii. **महाराष्ट्र:** महाराष्ट्र राज्य सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकूल जगा खरेदी अर्थ सहाय योजना पीएमएवाई-जी के तहत आवास के निर्माण के लिए 500 वर्ग फीट भूमि की खरीद के लिए भूमिहीन लाभार्थियों को 1,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

iv. **तमिलनाडु:** राज्य पीएमएवाई-जी के तहत आवास के निर्माण के लिए भूमिहीन लाभार्थियों को निःशुल्क भूमि प्रदान कर रहा है।